को इस्रायल में प्रधानमंत्री पद के लिए हुए चुनावों के दिन लंदन में बसे यहूदियों ने इस्रायली दूतावास को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें इस्रायली सेनाओं द्वारा फलस्तीनी जनता पर चलाये जा रहे दमन-चक्र को अविलम्ब रोकने व फलस्तीन को इस्रायली कब्जे से मुक्त करने की मांग की गयी थी। (देखें बॉक्स)।

दुनिया के स्तर पर उभर रही इन परिस्थितियों के दबाव का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जीतते ही एरियल शेरोन का स्वर बदल गया है। फलस्तीनी सवाल को हल करने के लिए इस्रायली फौजों को बेलगाम छोड़ देने की मांग उठाने वाला हेकड़ीबाज अचानक शान्ति की भाषा बोलने लगा है और राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का न्यौता दे रहा है। जाहिर है कि यह शेरोन का हृदयपरिवर्तन नहीं इन्तिफादा और दुनिया के जनगण के दबाव और संकटों से पैदा हुई मजबूरियां हैं।

इन तमाम अनुकूल परिस्थितियों को फलस्तीन की आजादी की हकीकत में तब्दील करना अब सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि इन्तिफादा जारी रहता है या नहीं। यह इन्तिफादा नेतृत्व के सामने एक चुनौती है कि वह गाजापट्टी और पश्चिमी तट के साथ ही इस्रायल के भीतर और अरब देशों के शरणार्थी शिविरों में रह रही फलस्तीनी आम आबादी को एकसूत्र में पिरोते हुए नये-नये कारगर उपकरणों का आविष्कार कर पाता है या नहीं। इन्तिफादा के जारी रहने के लिए यह भी जरूरी है कि पुराने अनुभवों से सीखते हुए पापुलर कमेटियों का प्रयोग नयी मंजिल में आगे बढ़ता रहे। साथ ही, सबसे अहम बात विचारधारात्मक रूप से परिपक्व होने और इसकी बुनियाद पर क्रान्तिकारी राजनीतिक संगठन के नेतृत्व में समूचे फलस्तीनी मेहनतकश अवाम को संगठित करना। यदि, इस बार यह सम्भव हो सका तो दुनिया के अनुकूल हालात को फलस्तीनी राष्ट्र की हकीकत में और कुछ खोये बिना तब्दील किया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि इसका दारोमदार बहादुर फलस्तीनी युवाओं पर अधिक है। इतिहास ने उनके कन्धों पर यह जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसे उन्हें पूरा करना ही होगा।

●

बोलते आंकड़े चीखती सच्चाइयां

➢ भारत का विदेशी व्यापार घाटा पिछले 40 सालों में 2485 करोड़ से बढ़कर 1,19,142 करोड़ रुपये हो गया। विदेशी कर्ज के सूद और किश्तों का भुगतान 296 करोड़ से बढ़कर 5,56, 530 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस दौरान कुल विदेशी देनदारी 6,75,672 करोड़ रुपये हो गयी। देश पर कुल विदेशी कर्ज 1960-61 में 250 करोड़ था जो 1998-99 के अंत में 9,800 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। (स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न अंकों के आधार पर 'फिलहाल' पत्रिका की गणना)

➢ पिछले दस वर्षों में भारत में कुल 1,02,785 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी आयी जबकि इसी अवधि में मुनाफा, सूद वगैरह के रूप में 1,01,781 करोड़ रुपये यानी आयी हुई विदेशी पूंजी का 99 प्रतिशत बाहर चला गया। (स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2000, भारत सरकार)

➢ रोजगार कार्यालय में दर्ज बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ 6 लाख हो गई है।

➢ आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के तहत निजीकरण और विनिवेश की तेज होती प्रक्रिया, छंटनी और तालाबंदी से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है और रोजगार के नये अवसर नहीं के बराबर दिखायी दे रहे हैं।

➢ श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000 के अनुसार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में हर वर्ष 20 लाख की बढ़ोत्तरी हो रही है।

➢ कुल रोजगार प्राप्त लोगों में से 8 या 9 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में हैं और शेष असंगठित क्षेत्र में हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं।

➢ नेशनल सैंपल सर्वे के ताजा नतीजों के मुताबिक 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर दो प्रतिशत और महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत घट गये। शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों में एक प्रतिशत की गिरावट आयी।

➢ यूनिसेफ की रिपोर्ट 'विश्व के बच्चों की स्थिति 1999' के मुताबिक

- 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के करीब 50 फीसदी भारतीय बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
- स्कूल जाने वाले बच्चों में से करीब 50 फीसदी बच्चे पांचवीं कक्षा में पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों में करीब आधे बच्चे ज्ञान के अनिवार्य न्यूनतम स्तर को भी नहीं प्राप्त कर पाते।
- स्कूल से बाहर निरक्षर बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है।
- भारत में कुल अशिक्षितों में दो-तिहाई महिलाएं हैं।
- दुनिया का हर तीसरा निरक्षर व्यक्ति भारतीय है और भारत ने दुनिया के सबसे बड़े निरक्षर देश के रूप में 21वीं सदी में प्रवेश किया है।

➢ शिक्षा पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले महज 10 फीसदी सुविधासम्पन्न लोगों की पढ़ाई-लिखाई पर खर्च हो जाता है। बाकी 30 फीसदी हिस्सा आबादी के शेष 90 फीसदी लोगों को मिलता है।

➢ 7.26 करोड़ बच्चे बेसिक शिक्षा से भी वंचित हैं।

➢ राजधानी दिल्ली में 54 प्राइमरी स्कूलों में पीने के पानी और 83 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 44 स्कूलों में चारदीवारी तक नहीं है।

➢ भारत में पांच वर्ष से कम का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है।

➢ करीब 20 करोड़ भारतीयों को आज भी सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता है और 70 करोड़ लोगों को ढंग का शौचालय नहीं उपलब्ध है।

➢ देश में 40 करोड़ लोग दो वक्त की रोटी से भी वंचित हैं जबकि सरकारी गोदामों में 430 लाख टन अनाज सड़ रहा है।

➢ पूंजीवाद की बुनियाद ही गैर-बराबरी पर टिकी है। इसका एक और प्रमाण यह है कि दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में गरीब बच्चों की संख्या 22 प्रतिशत है यानी हर पांचवां बच्चा गरीब है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 23 धनी देशों के करीब चार करोड़ सात लाख बच्चे गरीबी में रहते हैं।